

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त नियंत्रक प्राधिकारी / नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
- 2- वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आवास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 21 सितम्बर, 2011.

विषय: सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा भवन आदि निर्माणों का मानचित्र नहीं स्वीकृत कराये जाने पर उनके विरुद्ध चालान सम्बन्धी वाद दायर करने अथवा न करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध अवगत कराना है कि आर०बी०ओ० एक्ट 1958 की धारा (6) के प्राविधानतः विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र की अनुज्ञा के बिना किसी स्थल का विकास कार्य अथवा भवन आदि का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। आर०बी०ओ० एक्ट के निर्देश 1960 के निर्देश सं०-1 (झ) में उल्लिखित "व्यक्ति" की परिभाषा में भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं। अर्थात् विनियमित क्षेत्र, सीमान्तर्गत भवन आदि निर्माणों के लिये सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा भी नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र से आर०बी०ओ० एक्ट के नियमों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराकर अनुमति प्राप्त किया जाना वांछित है। आर०बी०ओ० एक्ट के विनियम, 1960 के विनियम संख्या-4(2) में किये गये उल्लेखानुसार सरकारी विभाग और निकाय/प्राधिकारी प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराते समय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने से मुक्त करेंगे परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी विभाग और स्थानीय निकायों द्वारा निर्माणों का मानचित्र नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत नहीं कराया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनियमित क्षेत्र, सीमान्तर्गत सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा भवन आदि निर्माणों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराये जाने पर उनके विरुद्ध आर०बी०ओ० एक्ट, 1958 के नियमों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

20/9